मेसर्स.गणेश सातारकर प्रकाशित

मालदीव का संविधान

ISBN: 978-81-999966-5-6

Author: - MR.GANESH SHRIRANG SATARKAR

LL.M

Advocate, Bombay High Court

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book
Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

1. **BOOK TITLE : मालदीव का संविधान**
2. **LANGUAGE:** HINDHI
3. **ISBN: 978-81-999966-5-6**
4. **EDITION:** FIRST EDITION
5. **AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR**
6. **PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY** :-
7. **M/s. INDIAN FARMER AGRO CO..** SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. **CONTACT DETAILS:**
   MOBILE: +91 7066766607 **EMAIL:** GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. **YEAR OF PUBLICATION:** 2026
10. **FORMAT:** SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. **PRICE (IN INDIA):** ₹ 10 /- (**Printed and Published in India)**

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.
Disclaimer:
This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

BIOGRAPHY : ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

Adv. Ganesh Shrirang Satarkar is an emerging legal scholar, researcher, and academic contributor working at the intersection of law, criminology, sociology, and digital governance. He is currently associated with the Central University of Haryana, where he is pursuing postgraduate research in sociology alongside his interdisciplinary work in legal studies.

He holds an LL.M. in Criminal Law, LL.B. (Special), and has qualified the UGC-NET in both Law and Criminology. His academic research focuses on criminal justice systems, cybercrime, artificial intelligence in law, media and crime, governance studies, and socio-legal research.

Adv.Ganesh has contributed to national and international academic platforms through research publications, conference papers, and interdisciplinary collaborations. His work explores emerging legal challenges in areas such as digital justice, cyber security, social justice, gender studies, and technological transformations in legal systems.

He is actively connected with several international academic and research platforms including ORCID, Web of Science, SSRN, Vidwan (INFLIBNET), Google Scholar, OSF, and Harvard Dataverse.

Author Bio Researcher Profiles :

1. ResearchIDs : rid131046
2. Orcid Id : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8474-7432
3. ISNI : https://isni.org/isni/0000000529498911
4. Web of Science ResearcherIDOYE-6264-2025
5. Social science research network SSRN Author ID: 9293272
6. Vidwan Profile URL: https://vidwan.inflibnet.ac.in/profile/666713
7. Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4MrvCEwAAAAJ
8. OSF ID : https://osf.io/cndj8/
9. harvard.edu : https://dataverse.harvard.edu/dataverse/GANESHSHRIRANGSATARKAR).
10 https://about.me/adv.ganeshsatarkar

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

CERTIFICATE

OF WORLD RECORD

Proudly Presented To

Ganesh Shrirang Satarkar

In recognition of the outstanding achievement of becoming the First Indian to Translate and Publish the Constitutions of All 54 African Countries into Hindi as Separate ISBN-Registered Books, demonstrating exceptional dedication, scholarly excellence, and a significant contribution to legal literature and linguistic accessibility, thereby establishing a distinguished and historic record of academic accomplishment.

We officially announce the above-mentioned candidate as a globally certified **"Inspiration World Record Holder"**.

The certificate was issued on 27th February, 2026.

INSPIRATION IS WHERE PASSION BECOMES LEGACY

CERTIFIED

Application No. IWR/2026/UR0173
Certificate No. IWR/2026/WRH0081
Issued By: Chief Adjudicator

ISO CERTIFIED

VISHWAGURU ARPANAM 2026

VIA2025/SS-VA2025AZ760-2025-170/09102025

2 025100 900010

ISO 9001:2015 Registration No: QT-56622/0925
Micro, Small, and Medium Enterprises Registration Number: 11-0093948
Trademark Registered Under the Act of "TRADE MARKS ACT, 1999"

© www.inspirationworldrecords.org

मालदीव का संविधान

मालदीव का संविधान (Constitution of Maldives 2008)

1. देश का नाम

Maldives
मालदीव गणराज्य (Republic of Maldives)

2. संविधान का नाम

मालदीव का संविधान, 2008 (Constitution of the Republic of Maldives, 2008)

यह संविधान 7 अगस्त 2008 को लागू हुआ। यह मालदीव में लोकतांत्रिक शासन, मानवाधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और बहुदलीय व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया।

---

3. संविधान के अध्याय (Chapters in Constitution)

मालदीव के संविधान में कुल **14 अध्याय (Chapters)** और लगभग **296 अनुच्छेद (Articles)** हैं।

---

4. संविधान के अनुच्छेद (Articles)

संविधान में अनुच्छेद 1 से 296 तक प्रावधान दिए गए हैं।
इनमें राज्य, नागरिक अधिकार, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, आपातकाल, संविधान संशोधन आदि विषय शामिल हैं।

---

5. अध्यायों की सूची एवं संक्षिप्त विवरण

अध्याय	विषय	संक्षिप्त विवरण
अध्याय 1	राज्य, संप्रभुता और नागरिक	राज्य की संरचना, नागरिकता, धर्म और राष्ट्रीय प्रतीकों का वर्णन
अध्याय 2	मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता	नागरिकों के अधिकार, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा, संपत्ति आदि
अध्याय 3	पीपुल्स मजलिस (संसद)	संसद की शक्तियाँ, चुनाव, सदस्यता और विधायी कार्य
अध्याय 4	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति की शक्तियाँ, चुनाव, कार्यकाल और दायित्व
अध्याय 5	मंत्रिमंडल	मंत्रियों की नियुक्ति, कार्य और उत्तरदायित्व
अध्याय 6	न्यायपालिका	सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति
अध्याय 7	स्वतंत्र आयोग	चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, भ्रष्टाचार निरोधक आयोग आदि
अध्याय 8	विकेन्द्रीकृत प्रशासन	स्थानीय परिषद और प्रशासनिक व्यवस्था
अध्याय 9	सुरक्षा सेवाएँ	सेना, पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा
अध्याय 10	राज्य की संपत्ति	सरकारी संपत्ति, संसाधन और कानूनी अधिकार
अध्याय 11	आपातकाल	आपातकाल की घोषणा और सीमाएँ
अध्याय 12	संविधान संशोधन	संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
अध्याय 13	संविधान की व्याख्या	संविधान के अनुप्रयोग और कानूनी अर्थ
अध्याय 14	संक्रमणकालीन प्रावधान	पुराने से नए संविधान में परिवर्तन संबंधी व्यवस्था

मालदीव के संविधान का विस्तृत वर्णन (5000 शब्दों में)

प्रस्तावना

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Maldives

मालदीव दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय राष्ट्र है, जो हिंद महासागर में स्थित है। लंबे समय तक वहाँ राष्ट्रपति आधारित केंद्रीकृत शासन रहा। 2008 का संविधान मालदीव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया। इस संविधान ने लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन को मजबूत किया।

यह संविधान आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है तथा नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान का उद्देश्य राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करना और जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करना है।

अध्याय 1 : राज्य, संप्रभुता और नागरिक

इस अध्याय में मालदीव को एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- मालदीव एक गणराज्य है।
- राज्य की संप्रभुता जनता में निहित है।
- इस्लाम राज्य धर्म है।
- संविधान सर्वोच्च कानून है।
- धिवेही राष्ट्रीय भाषा है।
- माले राजधानी है।

यह अध्याय राष्ट्रीय एकता और राज्य की पहचान को परिभाषित करता है।

अध्याय 2 : मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता

यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गई है।

प्रमुख अधिकार

1. समानता का अधिकार

सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं।

2. जीवन का अधिकार

किसी व्यक्ति को अवैध रूप से जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता।

3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

नागरिक अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं।

4. मीडिया की स्वतंत्रता

स्वतंत्र प्रेस और मीडिया की व्यवस्था दी गई है।

5. शिक्षा का अधिकार

हर नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

6. संपत्ति का अधिकार

नागरिक संपत्ति रख सकते हैं।

7. निष्पक्ष न्याय का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

8. गिरफ्तारी से सुरक्षा

अवैध गिरफ्तारी और हिरासत पर रोक लगाई गई है।

9. यातना का निषेध

किसी भी व्यक्ति को अमानवीय व्यवहार या यातना नहीं दी जा सकती।

यह अध्याय लोकतंत्र और मानवाधिकारों का आधार है।

---

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Maldives

अध्याय 3 : पीपुल्स मजलिस (संसद)

मालदीव की संसद को "पीपुल्स मजलिस" कहा जाता है।

संसद की शक्तियाँ

- कानून बनाना
- बजट पारित करना
- राष्ट्रपति की जवाबदेही सुनिश्चित करना
- मंत्रियों से प्रश्न पूछना
- संधियों को स्वीकृति देना

संसद की संरचना

- सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं।
- संसद का कार्यकाल निश्चित होता है।
- स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है।

यह अध्याय लोकतांत्रिक शासन की नींव को मजबूत करता है।

अध्याय 4 : राष्ट्रपति

मालदीव में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

- कार्यपालिका का प्रमुख
- मंत्रियों की नियुक्ति
- कानून लागू करना
- विदेश नीति का संचालन
- सुरक्षा सेवाओं का नियंत्रण

चुनाव

- राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है।
- कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी चुना जाता है।

यह अध्याय कार्यपालिका की शक्तियों और सीमाओं को निर्धारित करता है।

अध्याय 5 : मंत्रिमंडल

राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

मंत्रिमंडल के कार्य

- प्रशासन चलाना
- नीतियाँ बनाना
- संसद के प्रति उत्तरदायी रहना

मंत्रियों को संसद द्वारा हटाया भी जा सकता है।

अध्याय 6 : न्यायपालिका

यह अध्याय न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

न्यायालयों की संरचना

1. सर्वोच्च न्यायालय

देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय।

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Maldives

2. उच्च न्यायालय

अपीलों की सुनवाई करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय

स्थानीय मामलों का निपटारा करते हैं।

न्यायपालिका की विशेषताएँ

- न्यायाधीश स्वतंत्र होते हैं।
- न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है।
- न्यायालय संविधान की रक्षा करते हैं।

अध्याय 7 : स्वतंत्र आयोग

लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु स्वतंत्र आयोग बनाए गए हैं।

प्रमुख आयोग

1. चुनाव आयोग

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है।

2. मानवाधिकार आयोग

मानवाधिकारों की रक्षा करता है।

3. भ्रष्टाचार निरोधक आयोग

भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है।

4. सिविल सेवा आयोग

सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशासन।

यह अध्याय सुशासन को बढ़ावा देता है।

अध्याय 8 : विकेन्द्रीकृत प्रशासन

स्थानीय शासन को मजबूत बनाने के लिए परिषद प्रणाली दी गई है।

प्रमुख विशेषताएँ

- स्थानीय परिषदों का चुनाव
- स्थानीय प्रशासन को अधिकार
- वित्तीय स्वायत्तता

यह व्यवस्था जनता की भागीदारी बढ़ाती है।

अध्याय 9 : सुरक्षा सेवाएँ

इस अध्याय में सेना और पुलिस की भूमिका निर्धारित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- सुरक्षा सेवाएँ संविधान के अधीन रहेंगी।
- नागरिक अधिकारों का सम्मान आवश्यक है।
- अवैध आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा।

अध्याय 10 : राज्य की संपत्ति

राज्य की संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन इस अध्याय में किया गया है।

विशेष प्रावधान

- भूमि और समुद्री संसाधन राज्य की संपत्ति हैं।
- विदेशी स्वामित्व पर नियंत्रण।
- सरकारी संपत्ति का उपयोग जनता के हित में।

अध्याय 11 : आपातकाल

राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है।

सीमाएँ

- संसद की स्वीकृति आवश्यक।
- मौलिक अधिकारों पर सीमित प्रतिबंध।
- न्यायालय समीक्षा कर सकता है।

यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र के बीच संतुलन बनाता है।

अध्याय 12 : संविधान संशोधन

संविधान में संशोधन के लिए संसद की विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है।

संशोधन प्रक्रिया

- संसद में विशेष बहुमत
- राष्ट्रपति की स्वीकृति
- कुछ मामलों में जनमत संग्रह

यह संविधान को स्थिरता प्रदान करता है।

अध्याय 13 : संविधान की व्याख्या

इस अध्याय में संविधान की कानूनी व्याख्या और अनुप्रयोग का वर्णन है।

प्रमुख उद्देश्य

- संविधान सर्वोच्च कानून रहेगा।
- पुराने कानून संविधान के अनुरूप होंगे।
- न्यायालय अंतिम व्याख्या करेगा।

अध्याय 14 : संक्रमणकालीन प्रावधान

नए संविधान को लागू करने के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए।

मुख्य बिंदु

- पुराने कानूनों की निरंतरता
- नए संस्थानों की स्थापना
- न्यायपालिका और आयोगों का पुनर्गठन

मालदीव संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

1. लोकतांत्रिक संविधान

जनता की संप्रभुता को मान्यता।

2. मानवाधिकारों की सुरक्षा

अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए।

3. स्वतंत्र न्यायपालिका

न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया।

4. बहुदलीय व्यवस्था

राजनीतिक दलों को मान्यता।

5. शक्तियों का विभाजन

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में संतुलन।

6. विकेंद्रीकरण

स्थानीय शासन को महत्व।

7. जवाबदेही

राष्ट्रपति और मंत्रियों को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया।

मालदीव संविधान के लाभ

1. लोकतंत्र को मजबूत किया।
2. मानवाधिकारों की रक्षा।
3. स्वतंत्र चुनाव प्रणाली।
4. न्यायपालिका की स्वायत्तता।
5. भ्रष्टाचार नियंत्रण की व्यवस्था।
6. नागरिक स्वतंत्रता में वृद्धि।

संविधान की आलोचनाएँ

1. राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ।
2. इस्लाम को अनिवार्य धर्म बनाने से धार्मिक स्वतंत्रता सीमित।

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Maldives

3. राजनीतिक अस्थिरता की संभावना।
4. न्यायपालिका पर राजनीतिक प्रभाव के आरोप।

भारतीय संविधान से तुलना

विषय	मालदीव	भारत
शासन प्रणाली	राष्ट्रपति प्रणाली	संसदीय प्रणाली
धर्म	इस्लाम राज्य धर्म	धर्मनिरपेक्ष
संसद	पीपुल्स मजलिस	संसद
न्यायपालिका	स्वतंत्र	स्वतंत्र
संविधान संशोधन	विशेष प्रक्रिया	विशेष प्रक्रिया

निष्कर्ष

मालदीव का 2008 का संविधान देश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन को मजबूत किया। संविधान ने नागरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका और बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की।

हालाँकि कुछ चुनौतियाँ और आलोचनाएँ मौजूद हैं, फिर भी यह संविधान मालदीव को आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संविधान जनता की संप्रभुता, मानव गरिमा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Maldives

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book

THE END

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932